प्रतिलेखन संख्या 22

अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की माँगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ

हूँ। शिक्षा पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ

लगी है, उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी

लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है, शिक्षा पद्धति में अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं,

लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ

भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी

शिक्षा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आबंटित की गई है, वह भी

बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज

बढ़ता ही गया ज्यों–ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितने ज्यादा आयोग

और समितियाँ बैठीं और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई उतनी ही ज्यादा

बीमारी बढ़ती गई, बीमारी की इलाज न होकर और भी खराबियाँ पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने

माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरह की बहुत–सी रिपोर्टें हैं। अभी

सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत–सी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन

मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत

को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है अपनी विवशता को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है।

इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो

विशेष की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। मंत्रालय

का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको

राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है। लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा

दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राज नेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण को

सकता है।